• बड़ा निर्णय...

शिक्षा अनुशिक्षक योजना लागू करेगी

शिमला : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 6,297 प्री-प्राइमरी अनुभाग संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 60 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में 2,377 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्यों के शिक्षा विभाग को व्यापक प्रारंभिक बाल्य देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा विभाग प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम के सभी चार प्रारूपों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इन चार प्रारूपों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों, पूर्व में स्थापित प्री-प्राइमरी स्कूलों

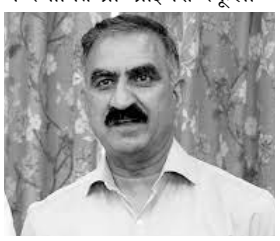

में पड़ रहे 5-6 वर्ष की आयु के बच्चे और प्री-प्राइमरी स्कूलों को शामिल किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 6,297 विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के नियमानुसार अनुशिक्षक रखेगी। सरकार की यह पहल बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि विद्यार्थियों को उनके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का समावेश करना प्रदेश सरकार का मूल ध्येय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के विभिन्न पदों को भरने जा रही है और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है।

• संपादकीय...

प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस

प्लास्टिक की थैलियां हर जगह हैं, किराने की दुकानों से लेकर खुदरा व्यापार तक, लेकिन वे हमारी प्यारी धरती मां के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। उन्हें ना केवल विघटित होने में सैकड़ों साल लगते हैं, बल्कि वे वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और महासागरों और परिदृश्यों को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान होता है। हालांकि, प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोकने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आंदोलन बढ़ रहा है। प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का बड़ा कारक है। दुनियाभर में हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि बता दें कि, जिस तरह इसे 20वीं सदी में विज्ञान का चमत्कार माना गया था, ठीक उसी तरह 21वीं सदी आते-आते यह चमत्कार हमारे लिए अभिशाप बन गया। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कई संस्थाएं और लोग अपने-अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। कोई अभियान चलाकर लोगों को पॉलीथिन के नुकसान बता रहा है, तो कोई फ्री में कपड़े की थैलियां बांट रहा है।

हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा फेंक दिया जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा महासागरों में चला जाता है, और इस प्रक्रिया में वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसके हानिकारक प्रभाव ने इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर और पेड़-पौधों को भी नहीं छोड़ा है। आज, बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे कि पेपर बैग, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कॉटन बैग, जालीदार बैग आदि। सबसे आम विकल्पों में से एक है कैनवास, कॉटन या अन्य सामग्रियों से बने दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बैग। ये बैग मजबूत, टिकाऊ होते हैं और इन्हें कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा विकल्प है पेपर बैग, जो बायोडिग्रेडेबल और रीसाइकिल करने योग्य होते हैं। जालीदार बैग, खास तौर पर फलों और सब्जियों को ले जाने के लिए उपयोगी होते हैं, हल्के होते हैं और इन्हें कई बार धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

■ **अनल पत्रवाल**
संपादक, हिमाचल अभी अभी

शराब ठेके ने बिगाड़ा गांव का माहौल

बंगाणा उपमंडल के डरोह में हाल ही में खोले गए शराब ठेके के विरोध में गुस्साई महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला। इन महिलाओं के साथ पहुंचे पंचायत प्रधान ने गांव में करीब तीन से चार लोगों पर अवैध शराब बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि इस मसले को लेकर भी वह लंबे अरसे से प्रशासन के समक्ष गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की है...

● **सुनैना जसवाल/बंगाणा**

उपमंडल बंगाणा के डरोह गांव में खुले शराब के ठेके को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया है। ठेके को बंद करने को लेकर महिलाओं ने डीसी ऊना को एक हफ्ते में दूसरी बार ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेताया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया, तो महिलाएं एकजुट होकर धरना देने के साथ साथ खुद ठेके की तोड़फोड़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगी।

बंगाणा उपमंडल के डरोह में हाल ही में खोले गए शराब ठेके के विरोध में गुस्साई महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला। इन महिलाओं के साथ पहुंचे पंचायत प्रधान ने गांव में करीब तीन से चार लोगों पर अवैध शराब बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि इस मसले को लेकर भी वह लंबे अरसे से प्रशासन के समक्ष गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की है। दूसरी तरफ अब गांव में जो ठेका खोल दिया गया है उसके चलते पास के ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट और मंदिर में आने जाने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि इसी क्षेत्र में घासनियां होने के कारण घास लाने वाली महिलाओं को भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं।

बंद हो ठेका नहीं तो करेंगी तोड़फोड़-आपको बता दें, यह कोई पहला मौका नहीं है जब शराब के ठेके को बंद करने की मांग को लेकर महिलाएं डीसी के समक्ष पहुंचीं हों। हफ्ते में दूसरी बार जिला प्रशासन को महिलाएं यहां पहुंचीं हैं। महिलाओं ने बताया कि डरोह गांव में शराब का ठेका खोल दिया है, जिसके कारण स्थानीय महिलाओं व बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठेका खुलने से बच्चों को नशे की लत लग जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रास्ते में 200 मीटर पर सीनियर सकेंडरी स्कूल व 50 मीटर पर आंगनबाड़ी केंद्र है। रास्ते से सुबह व शाम सैर को जाना पड़ता है। ठेका खुलने से महिलाओं को काफी मुशिकल पेश आती है। इतना ही नहीं इसी रास्ते से आगे राधा स्वामी सत्संग भवन है तथा 100 से 150 मीटर पर मंदिर भी है। महिलाओं ने बताया कि हमारी बेटियां पैदल ही स्कूल आती जाती हैं। ऐसे में कई लोग रेन शैल्टर में बैठ कर शराब पीते हैं और अपशब्द बोलते हैं, जिससे माहौल खराब हो गया है। महिलाओं ने डीसी ऊना से गुहार लगाई कि डरोह में खुले ठेके को तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा मजबूरन उन्हें खुद इस ठेके में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी और सड़क जाम करने को मजबूर होना पड़ेगा।

सेब की अर्ली वैरायटियां तैयार

मंडी : मंडी जिले में होने वाले करोड़ों रुपये के सेब के कारोबार के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं। उत्पादन कम होने से बगीचे खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 35 लाख सेब पेटी उत्पादित करने वाले मंडी जिले में इस बार 24.47 लाख सेब पेटी उत्पादन होने की उम्मीद है। मंडियों के आढ़ती भी कम दाम के ऑफर दे रहे हैं। इस कारण व्यापारी सेब बगीचों पर हाथ डालने से परहेज कर रहे हैं। कम दामों में खरीद के बावजूद मंडियों में कहीं सेब के दाम लुढ़क गए तो व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि सेब की सौदेबाजी पर विराम लगा हुआ है। रेड जून, टाइड मैन, समर क्वीन सेब मंडियों में जाने के लिए तैयार है। अभी तक बगीचों में बोली का दौर शून्य है। इस बार उत्पादन भी कम हुआ है। सेब की बोली लगाने के लिए व्यापारी बगीचों में नहीं घुस रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली के आढ़तियों ने व्यापारियों और बागवानों से बगीचे में ही 800 से एक हजार रुपये तक प्रति कार्टन सेब की खरीद कर बोली लगाने को कहा है। मंडी जिले के सेब उत्पादित क्षेत्रों में जून के मध्य में बगीचों के सौदे हो जाते थे, मगर इस बार कहानी कुछ और है। बागवानों यशवंत, राजू, केशव, यशपाल, देवेंद्र, मोहर, तेज सिंह, प्रेम, अनिल, नंदलाल, जीत कुमार, लीला प्रकाश, हेम सिंह ने बताया कि इस बार व्यापारी सेब के बगीचों का रुख नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में कोई कोल्ड स्टोर न होने से बागवान अपना सेब स्टोर करने में भी असमर्थ हैं। मंडी जिला में इस बार सेब का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 48,500 मीट्रिक टन है। जिले में एप्पल वैली करसोग, चुराग, चरखड़ी, निहरी, पण्डार, कमाद, शकोहर, रोहांडा, थमाड़ी, कुटाहची, डंग्यार, जहल, धंग्यारा, सलाहर, बगस्याड, थुनाग, जंजैहली, छतरी, सरोआ, शिल्हि बागी, बागाचनोगी, थाची और पंजाई में सेब का उत्पादन होता है।

• रेस्ट हाउस में...

रेंट रसीद की सुविधा

शिमला : लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित विश्राम गृहों और परिधि गृहों में अतिथियों का बेहतर आतिथ्य सत्कार सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विभाग द्वारा संचालित विश्राम और परिधि गृह में ठहरने वाले लोगों की सुविधा के लिए रेंट रसीद देने के निर्देश दिए गए हैं और यह सुविधा 1 जुलाई, 2024 से मिलनी आरम्भ हो जाएगी। इस सुविधा से विभाग को मिलने वाले राजस्व का बेहतर तरीके से संग्रहण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस रसीद का उपयोग व्यक्ति द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए भी किया जा सकेगा। डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में विभाग अपनी कार्यप्रणाली में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अंतर्गत परिधि गृहों और विश्राम गृहों में कैशलेस सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से परिधि गृह और विश्राम गृह में ठहरने वाले अतिथि क्यूआर कोड सहित अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे।

• बारिश से तबाही...

शिमला : हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने तबाही मचाई है। पहली ही बारिश से शिमला के निकटवर्ती स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। शहर के मल्याणा, चमियाना, भट्टाकुफर, मिनी कुफ्टाधार व शुराला सहित अन्य स्थानों पर भारी बारिश से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। कई जगह भूस्खलन से नुकसान हुआ है। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। भट्टाकुफर में पहाड़ी से गाड़ियों पर पत्थर गिर गए हैं। इससे सड़क किनारे पार्क एक गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मिनी कुफ्ताधार का रास्ता मलबा आने से नाले में तब्दील हो गया। शिमला शहर की ईदगाह कॉलोनी में भी नुकसान हुआ है।